"अपने भविष्य निर्माता हम स्वयं हैं", लोक सभा अध्यक्ष

शिविर: जयपुर, 21 अगस्त, 2016: ब्रिक्स महिला सांसद मंच की प्रथम बैठक का उद्घाटन लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा जयपुर में 20 अगस्त, 2016 को किया गया था। यह बैठक आज समाप्त हो गई है।

विदाई समारोह में शिष्टमंडल के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सांसदों के बीच वार्तालाप महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि नागरिकों और सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए संसद सदस्य बेहतर रूप से कार्य कर सकते हैं। उन्होंने सांसदों से आह्वान किया कि वे ब्रिक्स देशों में विद्यमान श्रेष्ठ प्रणालियों को जानें और उनसे लाभान्वित हों।

श्रीमती महाजन ने आशा व्यक्त की कि बैठक के दौरान तीन महत्वपूर्ण विषयों अर्थात् '*सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के बारे में परिदृश्य', 'सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति - नागरिकों को सहभागी बनाने में महिला सांसदों की भूमिका'* और *'जलवायु परिवर्तन की रोकथाम-वैश्विक सहयोग की अनिवार्यता'* पर किए गए विचार-विमर्श से महिला सांसद अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए नियमित रूप से मिलने हेतु प्रोत्साहित होंगी ताकि इस विषय पर अधिक गहन जानकारी प्राप्त हो सके और नीति निर्माताओं के रूप में उनके समक्ष आ रही समस्याओं और चुनौतियों पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर हमारे प्रयासों के संदर्भ में पहला विषय काफी महत्व रखता है और यह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का मार्ग है। उनका मानना था कि इन 17 लक्ष्यों और 169 सहयोजित लक्ष्यों में हमारे प्रयासों से देशों के भविष्य को परिवर्तित करने तथा प्रकृति के साथ सौहार्द स्थापित करते हुए अर्थपूर्ण विकास के मार्ग पर ले जाने की क्षमता है। उन्होंने महिला सांसदों को परामर्श दिया कि वे इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करें और यह उनका उत्तरदायित्व है कि वे सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन रणनीतियों और तंत्रों की भलीभांति निगरानी करें।

दूसरे विषय- 'सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति-नागरिकों को सहभागी बनाने में महिला सांसदों की भूमिका' पर श्रीमती महाजन ने कहा कि यह विकासात्मक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यदि इसे समानतापूर्ण, सतत और प्रभावी बनाना है तो विकास में महिलाओं व

पुरुषों का समावेश होना चाहिए। अत: सतत विकास की प्रणाली में समानता को मुख्य धारा में शामिल करना सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बैठक में शामिल एक अन्य महत्वपूर्ण विषय अर्थात् 'जलवायु परिवर्तन की रोकथाम- वैश्विक सहयोग की अनिवार्यता' का उल्लेख करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन संपूर्ण मानवता का प्रभावित करता है किन्तु साथ ही, हमारे पास विकासशील देशों के तौर पर हमारी अपनी चुनौतियां हैं।

समापन भाषण देते हुए राजस्थान की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने यह कहा कि महिला विधि निर्माता न केवल पुत्री, माता और बहन की भूमिका निभाती हैं। वे जन प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन का मार्गदर्शन भी करती हैं। इसके साथ-साथ करूणा और दयाभाव भी रखती हैं। यह उन्हें सक्षम अभिभावक और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। भिन्न-भिन्न रूप से विकसित ब्रिक्स देशों को और अधिक समृद्ध बनाए जाने की आवश्यकता है। इसे हासिल करने के लिए विकास प्रक्रियाओं को निरंतर बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला विधि निर्माताओं के बीच सहभागिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भारत की लोकतांत्रिक परम्परा से सभी अवगत है उन्होंने कहा कि गरीबी और भूख की समस्या को दूर करने, स्वास्थ्य सुधार तथा पर्यावरण संरक्षण करने में जन प्रतिनिधि पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने प्रधामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिकोण- सबका साथ, सबका विकास का भी उल्लेख किया। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग को सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और कार्यान्वयन की भूमिका दी गई है।

राजस्थान का उल्लेख करते हुए श्रीमती राजे ने कहा कि यहां का विकास सामाजिक न्याय, प्रभावी शासन और रोजगार सृजन पर आधारित है। 2008 में, राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लक्ष्य पर आधारित भामाशाह नामक एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम शुरू किया। राजस्थान के वित्तीय समावेशन प्रयासों में बर्बादी, चोरी-चकारी और रिश्वतखोरी के बिना नागरिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों का हस्तांतरण सुनिश्चित किया गया है। अन्य कार्यक्रमों में राजस्थान के कौशल विकास तथा कार्यक्रमों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। जल स्वाबलंबन अभियान एक जन आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। इसमें जन साधारण, कॉर्पोरेट घराने, सुरक्षा सेवाएं तथा नागरिक समाज पारम्परिक जल संचयन सरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए एकजुट हुए हैं।

इससे पहले प्रतिभागियों ने 'जलवायु परिवर्तन की रोकथाम- वैश्विक सहयोग की अनिवार्यता' विषय पर चर्चा में भाग लिया। प्रतिभागी इस बात पर एकमत थे कि जलवायु परिवर्तन समूची मानवता के लिए एक गंभीर तथा वैश्विक चुनौती बन गया है और इसके हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए विश्व स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से महिलाएं तथा बच्चे सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। अतएव, यह अनिवार्य है कि सभी देश स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग करें और कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए समय रहते कदम उठाएं। प्रतिभागियों ने विकसित देशों से आह्वान किया कि वे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निबटने के लिए विकासशील देशों को और अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। उनका यह भी मत था कि महिलाएं अपने स्थानीय ज्ञान व विशेषज्ञता तथा पर्यावरण के प्रति अधिक जागरुक होने के कारण इस दुष्कर चुनौती से निपटने के बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। प्रतिभागियों की इस बात पर भी सर्वसम्मति थी कि महिलाएं विशेषकर महिला सांसद प्रभावी विधान के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं।